

११

संशोधन
संख्या / १२-XIX-२/१९ खाद्य/२०१२

प्रेषक,

सुबद्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक । जून, २०१२

विषय:- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखण्ड के कार्यालय भवन के किराये स्वीकृति का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या संख्या २४४ / १२-XIX-२/१९ खाद्य/२०१२ दिनांक ३१ मई, २०१२ के संदर्भ में जारी शासनादेश के क्रम में अपने पत्र संख्या ५८७ / रा०आ०उ०स० दिनांक ०१.०६.२०१२ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि भवन स्वामी द्वारा जारी उक्त शासनादेश के बिन्दु सं० ०४ एवं ०५ को स्वीकार न किये जाने पर उक्त शासनादेश को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के बिन्दु सं० ४ एवं ५ को इस सीमा तक शिथिल किया जाता है कि स्वीकृति किराया बृद्धि पर तभी विचार किया जायेगा जबकि शासकीय दरों में बृद्धि की गयी हो इससे पूर्व कदापि किराया बृद्धि पर विचार किया जाना मान्य नहीं होगा, इस आशय का अनुबन्ध पत्र भवन स्वामी से यह लिखित रूप में प्राप्त करा लिया जाय तथा साथ ही बिन्दु सं० ०५ को इस सीमा तक शिथिल किया जाता है कि भवन स्वामी के साथ किराया सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र ०५ वर्ष के स्थान पर जब तक भवन विभाग द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है तब तक ११-११ माह का अनुबन्ध पत्र प्राप्त कर लिया जाय इस पर भवन स्वामी द्वारा किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही अथवा अन्य दावों पर कोई शिथिलीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है

अतः शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित पढा एवं समझा जायेगा।

भवदीय,

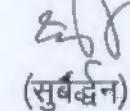
(सुबद्धन)
सचिव

संख्या 246 / ११-XIX-२/१९ खाद्य/२०१२ तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समन्यक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,


(सुर्वद्वन्द्व)

०१/६/१८

सचिव